लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *313

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र मिलों का कार्यकरण

***313. श्री राजकुमार रोत:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कितनी वस्त्र मिल कार्यशील हैं;

(ख) उक्त मिलों में से वर्तमान में कौन-कौन सी और कितनी मिलें बंद हो चुकी हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में सरकारी और निजी क्षेत्र की कितनी मिलें कार्यशील हैं और सरकार द्वारा उक्त मिलों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का इन मिलों के बंद होने के कारण इन क्षेत्रों में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इन बंद मिलों को पुन: शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो बंद मिलों को कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:</u>

(क) और (ख): राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में प्रचालनशील और गैर-प्रचालनशील मिलों का ब्यौरा (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई 2022-23) के अनुसार) **अनुबंध-1** में दिया गया है। वस्त्र मिलों के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण की कमी, खराब प्रबंधन, लागत में वृद्धि, कार्यशील पूंजी की कमी आदि कारक शामिल हैं।

(ग): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2022-23 के अनुसार, डूंगरपुर में 3 निजी मिलें और बांसवाड़ा जिले में 4 निजी मिलें हैं। इन जिलों में केंद्र सरकार की कोई मिल कार्यशील नहीं है।

सरकार, वस्त्र उद्योग में पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत, बांसवाड़ा जिले में 3 इकाइयों को 93 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ): सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अनुकूल इको सिस्टम बनाने हेतु विभिन्न पहलें की हैं। मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:-

i) सरकार ने ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर सात प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

ii) सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इससे वस्त्र क्षेत्र को साइज और पैमाना प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

iii) सरकार ने भारत में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में मौलिक (फंडामेंटल) और अप्लाइड दोनों तरह के अनुसंधान और संवर्धन एवं बाजार विकास गतिविधियों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के प्रभाव को बढ़ाया गया। तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में कुशल और शिक्षित जनशक्ति तैयार करने हेतु अनुसंधान तथा विकास के लिए निधि आवंटित की गई है।

iv) इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है जैसे कि समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, जूट (आईसीएआरई - उन्नत खेती और उन्नत प्रक्रिया प्रक्रिया), सिल्क समग्र 2.0, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) आदि जो विशेष रूप से देश में स्वदेशी वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

अनुबंध-1

चार राज्यों (मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान) में प्रचालनशील और गैर- प्रचालनशील मिलों सहित कुल मिलों का विवरण

राज्य	कुल मिलें	प्रचालनशील मिलें	गैर-प्रचालनशील मिलें
मध्य प्रदेश	237	224	13
गुजरात	3,481	2,544	937
छत्तीसगढ़	27	27	0
राजस्थान	1,779	1,633	146

* वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2022-23 के अनुसार

*****